

सीटू जनरल काउंसिल द्वारा पारित प्रस्ताव

कामरेड पी. राममूर्ति

धनबाद में 23 से 25 सितंबर 1988 के बीच आयोजित जनरल काउंसिल की यह बैठक सीटू के संस्थापक महासचिव का. पी. राममूर्ति के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है। उनका निधन 15 दिसंबर 1987 को हुआ। का. पी. राममूर्ति का निधन सीटू, ट्रेड यूनियन और देश के कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में शुरू किया था, जैसे जैसे उन्होंने अपने समय में मार्क्सवादी-लेनिनवादी समझ के साथ राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष में आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे वे सबसे अगुआ और अटल साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों का प्रतिनिधित्व करने लगे और यह प्रक्रिया उन्हें अंततः कम्युनिस्ट आंदोलन के कतारों में ले आई। अपने प्रतिभा और मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पण के कारण वे उस समय के स्वीकृत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। बाद में वे उसके केन्द्रीय समिति और सेक्रेटरी-रिपट के सदस्य बन गये। वर्ग संघर्ष के रास्ते पर प्रतिबद्धता से आगे बढ़ते हुए मार्क्सवादी जोश खरोश के साथ उन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन में सुधारवादी और सहयोगवादी प्रवृत्तियों का मुकाबला किया। सी. पी. आई. (एम.) के गठन के साथ वे इसके केन्द्रीय कमेटी और पोलिन ब्यूरो के सदस्य बन गए और कई वर्षों तक इसी पद पर बने रहे।

अपने जीवन काल में का. पी. राममूर्ति उन सभी तथ्यों और वास्तविकताओं से भली भांति परिचित थे जिससे मजदूर वर्ग और भारतीय जनता पिछले कई सालों से जुझ रही थी। वे देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन के अग्रणी नेता थे और एटक के जाने माने हस्ती बन गए। वे साम्राज्यवादी चंगूल से देश को आजाद कराने के संघर्ष में और फिर आजादी के बाद बुर्जुवा-भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ मजदूरों एवं लोगों के संघर्ष में, मजदूर वर्ग एवं ट्रेड यूनियन आंदोलन की भूमिका के बारे में क्रांतिकारी चेतना विकसित करने के कारण ही वह एक सफल नेता के रूप में उभरे। वर्ग संघर्ष का लाइन तथा जनवाद की रक्षा एवं समाजवादी समाज की स्थापना के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए मजदूरों के बढ़ते राजनीतिकरण के लिए प्रतिबद्ध का. पी. आर ने ट्रेड यूनियन आंदोलन में सुधारवादी और सहयोगवादी रूढ़ानों का भी समान मार्क्सवादी-जोश-खरोश के साथ मुकाबला किया और मजदूर तबकों का विश्वास प्राप्त करते गए। 1970 में सीटू के गठन के समय वे स्वाभाविक रूप से महासचिव बने। महासचिव के रूप में का. पी. आर के समय काल में ही सीटू संगठन को अपना रूप मिला, इसका प्रभाव तेजी से फैला और वह भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन का एक अग्रणी केन्द्र के रूप में उभरा।

उनकी परिवक्ता और बहुमुखी प्रतिभा और उद्योगों की तकनीकी समस्या को आसानी से समझ लेने की क्षमता तथा सरकार और मालिकों के दमन चक्र का सामना करने का उनका अटूट साहस और ट्रेड यूनियन की एकता के लिए उनका सतत संघर्ष के कारण उनकी प्रतिष्ठा सीटू से बाहर भी असीमित रूप से बढ़ी और वे देश के कामगार तबकों के असाधारण नेता के रूप में स्थापित हुए। पहले ब्रिटिश शासन और इसके बाद कांग्रेसी राज्य के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए कामरेड पी आर को अनेक बार जेल में डाला गया। जनरल काउंसिल शपथ लेती है कि वह का. पी. आर के अधूरे कामों को, जिसके लिए उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया था, पूरा करेगी। काउंसिल उनकी याद में अपने लाल भण्डे को भुकाती है और उन्हें हादिक श्रद्धांजलि देती है।

कामरेड कृष्णपद घोष

जनरल काउंसिल सीटू के कार्यकारिणी समिति के सदस्य और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय समिति के भूतपूर्व सदस्य का. कृष्णपद घोष जिनका निधन 30 दिसम्बर 1987 को हुआ पर गहरी संवेदना व्यक्त करती है। का. कृष्णपद घोष बहुत कम उम्र में बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे और 1935 में कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ गए। वह 1964 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के बाद इसमें शामिल हो गए।

उन्होंने अपना ट्रेड यूनियन गतिविधियों की शुरूआत सैकमबी फार्मर, गोदी और बंदरगाह एवं अन्य मजदूरों को संगठित करते हुए की एवं विभिन्न उद्योगों के कई ट्रेड यूनियन संगठनों के नेता बने। उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन को मजदूर-वर्ग के क्रांतिकारी परम्पराओं की दिशा में निर्देशित किया। 1970 में सीटू की स्थापना के समयकाल से ही वह इसके कार्यकारिणी के सदस्य रहें और इस पद पर अंतिम काल तक बने रहें। का. कृष्णपद घोष उन चुने गिने अग्रिम पंक्ति के नेताओं में से थे जो 1972 से 77 के दरमियान बंगाल में अर्द्ध फासी आतंक राज के दौरान अपने ज़िदगी को खतरे में डालकर मजदूरों को उनके संघर्ष में रास्ता दिखाया और राज्य में सीटू को एक ठोस आधार पर खड़ा किया। यह जनरल काउंसिल कामरेड कृष्णपद घोष को भावमयी श्रद्धांजलि देती है और उनकी याद में लाल भण्डे को भुकाती है।

शहीदों को श्रद्धांजलि पर

सीटू जनरल काउंसिल की यह बैठक पंजाब में खेतिहर मजदूरों के नेता का. हरवंश सिंह बीका, अमृतसर जिले के लोकतांत्रिक आंदोलन के समर्पित कार्यकर्ता का. सुच्चा सिंह

नारला, का. वालबिन्दर सिंह जो खालिस्तानी आतंकवादियों के शिकार हुए, का. केवल सिंह का. बलकार सिंह, का. जागीर सिंह एवं अन्यो को, श्रद्धांजलि अर्पित करती है। सीटू देश की एकता और अखंडता की रक्षा में अलगाववादी ताकतों का मुकाबला करने में इन शहीदों के बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद करती है।

जनरल काउंसिल उन सभी कामरेडों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के दौरान दार्जिलिंग और त्रिपुरा में पृथकतावादी ताकतों का मुकाबला करते हुए अपने जान की बाजी लगा दी।

शोक संदेश पर

जनरल काउंसिल उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करती है जिन्होंने हाल में मजदूरों, किसानों और मेहनतकशों के संघर्ष के दौरान पुलिस और गुंडों के हमले में अपने जान की कुर्बानी दे दी।

नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष पर

सीटू की जनरल काउंसिल की यह मीटिंग, द. अफ्रीका में नस्लवाद का बढ़ावा देने तथा नामीबिया में सैनिक हस्तक्षेप के लिए रंग भेदी बोथा सरकार की भर्त्सना करती है। मीटिंग द. अफ्रीका और नामीबिया में लोकतन्त्र और आजादी के लिए चलाए जा रहे आंदोलनों को कुचलने के लिए बर्बतापूर्ण दमनात्मक कार्रवाइयों की निंदा करती है।

साथ ही जनरल काउंसिल दुनिया के सबसे बदनाम और प्रतिक्रियावादी शासन की शर्मनाक ढंग से हिमायत करने के लिए ब्रिटिश और अमरीकी साम्राज्यवाद की निंदा करती है। जनरल काउंसिल ए एन सी और स्वापो की अगुआई में नस्लवादी निजाम के खिलाफ सतत आंदोलन चलाने के लिए नामीबिया और द. अफ्रीका की जनता के प्रति एकजुटता का इजहार करती है।

जनरल काउंसिल, पिछले 18 जुलाई को नेलसन मंडेला के 70वें जन्मदिन पर उनके रिहाई की मांग को लेकर तमाम देशों नस्लवाद परस्त निजाम के खिलाफ उठे जबर्दस्त विद्रोह के प्रति संतोष व्यक्त करती है। यहां तक कि नस्लवादी हुकूमत को संरक्षण देने वाले देश अमरीका और ब्रिटेन में भी लाखों लोगों ने मंडेला की अविलम्ब रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया।

जनरल काउंसिल नेल्सन मंडेला के 70वें जन्म दिवस को उनकी रिहाई की मांग दिवस के रूप में मनाने के सीटू की अपील को सफल बनाने के लिए सीटू यूनियनों का अभिनन्दन करती है। यह भारतीय ट्रेड यूनियन समिति की द. अफ्रीका की जनता के संघर्ष के समर्थन में फण्ड जुटाने के लिए सराहना करती है तथा

नस्ली निजाम के खिलाफ चल रहे आंदोलनों के समर्थन के प्रति एक बार फिर एकजुटता जाहिर करने के लिए तमाम ट्रेड यूनियनों का आह्वान करती है।

खाड़ी युद्ध के वार्ता पर

यह जनरल काउंसिल, ईरान-इराक युद्ध बंद करने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को स्वीकार करने तथा राष्ट्र संघ की पहलकदमी पर शांति वार्ता शुरू करने के लिए ईरानी सरकार का स्वागत करती है। जनरल काउंसिल आशा करती है कि शांति वार्ता में उत्पन्न बाधाओं को सुलझा लिया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र संघ तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन जिनके ईरान-इराक दोनों ही सदस्य हैं, निर्णायक भूमिका निभायेंगे। युद्ध की आड़ में अमरीका और इसके सहयोगियों ने खाड़ी में अपने सैनिक ठिकानों में बढ़ोत्तरी किए हैं। सीटू यह मांग करती है कि खाड़ी क्षेत्र से अमरीका तथा उसके गठजोड़ तत्काल अपने तमाम नौसैनिक बल को वापस लें।

शांति के लिए संघर्ष पर

घनवाद में सम्पन्न सीटू जनरल काउंसिल की यह बैठक अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर समीक्षा के दौरान यह नोट करती है कि कार्यकारिणी समिति की पिछले बैठक के बाद के इस समय में गोर्वाचिव और रीगन के बीच मध्यम और अल्प दूरी के मिसाइलों को नष्ट करने संबंधित 8 दिसम्बर 1987 को हुए आइ एन एफ समझौता स्वागत योग्य उपलब्धी है। मीटिंग में यह तय पाया गया कि यह शांति के लिए बढ़ते विश्वव्यापी आंदोलनों के कारण उत्पन्न दबाव तथा सोवियत संघ द्वारा पेश किए गए एक के बाद एक शांति प्रस्तावों के कारण संभव हो पाया।

बहरहाल बैठक की यह समझदारी है कि इसमें संतोष करने का कोई कारण नहीं है। यह गौरतलब है कि रीगन प्रशासन ने अब तक एस डी आई कार्यक्रम को छोड़ने से इंकार कर दिया है। जो कि नाभिकीय विनाश का सबसे भयानक खतरा है। दूसरे शिखर सम्मेलन, जिसमें लम्बी दूरी के मिसाइलों में 50 प्रतिशत कटौती पर विचार करना था, कोई नतीजा नहीं निकला। आइ. एन. एफ. समझौता के बाद भी अमरीका तथा इसके नाटो गुट के देश नाभिकीय हथियारों को और भी आधुनिक बनाने में लगे हैं। ये सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए संयुक्त रूप से अत्याधुनिक एंटी टैंक न्युक्लियर मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं। इस अवधि में अमरीकी साम्राज्यवादियों की यह मुहिम निरस्तीकरण के लिए उठ रहे विश्व व्यापी अपील की अवहेलना कर उसके युद्ध की लगातार तैयारी और पूरी दुनिया पर प्रभुत्व कायम करने की मंशा को ही उजागर करता है। इसलिए, सीटू जनरल काउंसिल की यह बैठक सीटू यूनियनों का आह्वान करती है कि वे अमरीका द्वारा एस डी आई कार्यक्रम को वापस लेने की तथा लम्बी दूरी के मिसाइलों की खात्मे की मुख्य मांग

पर अधिक से अधिक मजदूर व ट्रेड यूनियनों को लामबंद करते हुए शांति के लिए संघर्ष के निर्माण में अपने प्रयासों को तेज करें.

फेदाइयान और तुदेह पार्टी के नेताओं पर लगे मृत्युदण्ड पर

सीटू की यह जनरल काउंसिल अधिवेशन, इरान के इस्लामी प्रशासन द्वारा फेदाइयान और तुदेह पार्टी के नेताओं पर लगाये गए फांसी दण्ड की तीव्र भर्त्सना करती है. पिछले चार महीने के अंतर्गत आरगेनाइजेशन आफ इरानियन पिपुल्स फेदाइयान (मेजोरिटी) और तुदेह पार्टी के चार प्रमुख नेताओं को फांसी दिये जाने की सरकारी तौर पर पुष्टि कर दी गई है. इसके अलावा दूसरे 55 राजनैतिक कैदियों को फांसी लगा दी गयी या उन्हें फांसी लगाये जाना है. साथ ही 70 और राजनैतिक कैदियों पर लगे मृत्युदण्ड की पुष्टि तथाकथित धर्मतांत्रिक ताना-शाही इस्लामी अदालत ने किया. जिन क्रांतिकारी नेताओं को फांसी दण्ड दिया गया है उनमें तुदेह पार्टी के सचिव और केन्द्रीय समिति के सदस्य भी शामिल हैं. सीटू जनरल काउंसिल फांसी दिये जाने की घटनाओं की निंदा करती है तथा मजदूर वर्ग से इस हत्या कांड के खिलाफ तथा राजनैतिक कैदियों की अविलम्ब रिहाई एवं जनतांत्रिक अधिकारों के पुनर्स्थापना के समर्थन में अपनी आवाज बुलन्द करने का आह्वान करती है.

अफगानिस्तान पर

सीटू जनरल काउंसिल का यह अधिवेशन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सम्पन्न और सोवियत संघ तथा अमरीका द्वारा गारण्टी किए गये जनिवा समझौते का स्वागत करने के साथ-साथ अमरीका के सीधे संरक्षण में इस समझौते का उल्लंघन करने एवं अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुलह की प्रक्रिया को तहस-नहस करने की पाकिस्तान की फौजी हुकूमत की चालों पर गहरी चिंता प्रकट करती है. इस समझौते के शर्तों का उल्लंघन करने के क्रम में अभी भी पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के लिए अफगान विद्रोहियों को प्रशिक्षण दे रहा है तथा उन्हें हथियार से लैस कर रहा है.

जनरल काउंसिल इस बात पर रोष प्रकट करती है कि जब अफगानिस्तान, सरकार तनाव को दूर करने का हर संभव प्रयास कर रही है तथा हजारों शरणार्थियों के लौटने के साथ ही उसके राष्ट्रीय सुलह की प्रक्रिया को भारी समर्थन मिल रहा है तथा जब सोवियत संघ भी समझौते के शर्तों के मुताबिक अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला रहा है वैसे समय में अमरीका और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अस्थिरता फैलाने की साजिश में लगी हैं और अफगानिस्तान की क्रांतिकारी सरकार को गिराने और अस्थिरता फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं. जनरल काउंसिल इस समझौते का उल्लंघन की निंदा करती

है और मजदूर वर्ग और जनतांत्रिक ताकतों से अपील करती है कि सम्राज्यवादी साजिशों को नाकाम करने के लिए अपनी आवाज बुलन्द करें.

तमिलनाडु में अविलंब चुनाव की मांग पर

यह जनरल काउंसिल तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन की पहली अवधि की समाप्ति के बावजूद केन्द्र सरकार की राज्य विधान सभा चुनाव न कराने के प्रयास की निंदा करती है. जनरल काउंसिल इस बात पर रोष प्रकट करती है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद केन्द्र सरकार ने कई बार चुनावों की तारीख की घोषणा का संकेत दिया किन्तु हर बार घोषणा को स्थगित कर दिया गया.

जनरल काउंसिल यह अनुभव करती है कि राज्य में चुनाव टालने के पिछे चुनावी राजनीति काम कर रही है जिसका उद्देश्य सत्तारूढ़ कांग्रेस (आई) की संकीर्ण दलीय हितों की संरक्षण देना है. जनरल काउंसिल राज्य में चुनाव की तारीख की अविलंब घोषणा की मांग करती है तथा जनतांत्रिक आवाम से इस मांग के समर्थन में आवाज बुलन्द करने की अपील करती है.

सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण पर

सीटू की जनरल काउंसिल की यह बैठक विश्व बैंक के दबाव में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को गिराने और उसके निजीकरण करने की भारत सरकार की लगातार मुहिम की तीव्र निंदा करती है.

सीटू के छोटे सम्मेलन के बाद से जिसमें देशी इजारेदारों और बहु राष्ट्रीय कंपनियों के हितों की रक्षा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण करने के खतरे के बारे में अगाह किया गया था, भारत सरकार अपने इस अभियान में बिना रुके काफी आगे बढ़ चुकी है. एक के बाद एक सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों की बंदी और अधिगृहित इकाइयों को डिनॉटिफिकेशन एक नियमित खतरा बनता जा रहा है. स्वतंत्र व स्वायत्त प्रबंधन के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्रों पर से संसदीय नियंत्रण धीरे धीरे खत्म किए जाने की साजिश जारी है. अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के ईकाइयों के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर में इजारेदारों तथा व्यापारी घरानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र की एक संभावनापूर्ण इकाई स्कूटर इंडिया के निजीकरण की घोषणा भी की जा चुकी है. भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तालोजा यूनिट के प्रबंधन तथा अधिकांश शेयरों को एक भारतीय इजारेदार तथा एक बहु-राष्ट्रीय कंपनी को देने का निर्णय और भी खतरनाक है. याद रहे कि विश्व बैंक ने अपने हॉल के रिपोर्ट में इस्पात उद्योग समेत भारी और बुनियादी उद्योगों के अन्तर्गत आने वाले अनेक सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों का निजीकरण का सुझाव

दिया है. यह भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को धक्का पहुंचाने का साम्राज्यवादी साजिश का ही एक हिस्सा है.

जनरल कांउंसिल, सार्वजनिक उद्योगों को बचाये रखने तथा आत्म निर्भरता को बरकरार रखने के लिए चलाए जा रहे संघर्ष के लिए सार्वजनिक उद्योगों के कामगारों का अभिनन्दन करती है. 14-16 मार्च की शानदार हड़ताल के कारण हासिल एकता को और मजबूत करने तथा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि सरकार की इस नीति को प्रभावी ढंग से नाकाम बनाने के लिए श्रवाम को लामबंद किया जा सके.

दार्जिलिंग समझौता पर

सीटू की यह जनरल कांउंसिल की बैठक केन्द्र सरकार, प. बंगाल की वामपंथी सरकार तथा जी. एन. एल. एफ. के बीच हुए त्रिपक्षीय दार्जिलिंग समझौता का स्वागत करती है. जनरल कांउंसिल का विचार है कि विकास के पूंजीवादी रास्ते अपनाने के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ेपन के कारण पहाड़ी लोगों में असुरक्षा की भावना उभरा जी. एन. एल. एफ. ने इसका फायदा उठाते हुए लोगों को अलगाववादी विद्रोह में भोंक दिया. केन्द्र सरकार इस आंदोलन के पृथकतावादी प्रवृत्ति तथा इसका साम्राज्यवादी एजेन्सियों के साथ सम्पर्क को अनदेखा करते हुए उसने शुरू शुरू में वामपंथी सरकार को गिराने के उद्देश्य से आंदोलन को भड़काया. हिंसक आंदोलन के बीच करीब तीन वर्षों के दौरान लगभग एक हजार लोग मारे गए तथा कई हजार लोग बेघर हो गए. साथ ही कई करोड़ रुपये की सम्पत्ति को नष्ट कर दिया गया.

जनरल कांउंसिल देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए चाय वागानों के मजदूरों को पृथकतावादी उपद्रवकारियों से डट कर मुकाबला करने के लिए वधाई देती है. साथ ही यह बैठक प. बंगाल के वामपंथी सरकार को इस मसले के बुनियादी सिद्धांतों पर अटल रहने तथा इस क्षेत्र की कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए समुचित प्रशासनिक कदम उठाने के लिए बधाई देती है. कामगारों के बहादुराना संघर्ष तथा वामपंथ सरकार द्वारा सही कदम उठाने के कारण ही यह समझौता सम्पन्न हो पाया. जनरल कांउंसिल आशा करती है कि इस समझौते को लागू करने के साथ ही दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों में शांति कायम हो जाएगी तथा देश की एकता तथा अखंडता को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी.

59वां संविधान संशोधन पर

धनवाद में सम्पन्न सीटू जनरल कांउंसिल की यह बैठक पंजाब में आंतकवादी गतिविधियों को कुचलने के नाम पर आपातस्थिति लागू करने की शक्ति हथियाने के लिए संविधान में 59वें संशोधन पारित करने के लिए भारत सरकार की तीव्र भर्त्सना करती है. जनरल कांउंसिल भारत के मजदूर वर्ग तथा

जनता को सचेत करती है कि 59वें संविधान संशोधन से सरकार ने पूरे देश में आपात स्थिति लागू करने की शक्ति प्राप्त कर चुकी है. गौर करने की बात है कि 1975 में स्व. प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक कलह के प्रावधानों का दुरुपयोग करके पूरे देश में इमरजेन्सी लगाकर जनता को तमाम बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया था. जनता सरकार ने उस प्रावधान को हटा दिया था. अब सरकार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर डटे हुए भारत बंद के दौरान तमाम वामपंथी तथा धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियों और जन संगठनों की हिस्सेदारी से उत्पन्न वैसी ही परिस्थितिको देखते हुए राजीव गांधी ने फिर से उन प्रतिगामी प्रावधानों को लागू किया है. सरकार की बढ़ती अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को देखते हुए सरकार के इस अश्वासन पर कि जरूरत पड़ने पर ही केवल पंजाब में इस 59वें संशोधन के प्रावधानों का इस्तेमाल किया जायेगा, विश्वास नहीं किया जा सकता. सरकार जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के लिए इमरजेन्सी लगाने की अधिकार हासिल कर ली है. जनरल कांउंसिल सीटू के सभी यूनियनों का आह्वान करती है तथा दूसरे तमाम यूनियनों तथा जनतांत्रिक ताकतों से अपील करती है कि वे 59वें संविधान संशोधन को रद्द करने के लिए अपनी संगठित आवाज को बुलन्द करें.

त्रिपुरा पर

धनवाद में आयोजित सीटू की यह जनरल कांउंसिल की बैठक त्रिपुरा की बदतर स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर करती है. राज्य में चुनाव के ऐन वक्त पर सैनिक और अर्द्ध सैनिक बलों के प्रयोग से वामपंथी मोर्चे को सत्ता से हटाकर धांधली भरी चुनाव के जरिए सत्ता हथियाने के बाद कांग्रेस सरकार ने राज्य में अर्द्ध फासी आतंक कायम की है. लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई समितियों को समाप्त कर दिया गया है. सी. पी. एम., सीटू और दूसरे वामपंथी शक्तियों के कार्यकर्त्ताओं और समर्थकों पर रोज घातक हमले हो रहे हैं. जिस कारण बड़ी संख्या में वामपंथी कार्यकर्त्ता मौत के घाट उतारे जा चुके हैं. उनके घरों को जलाये जा रहे हैं. बड़ी संख्या में लोग तथा कामगार बेघर हो गए हैं. असामाजिक तत्वों द्वारा उनके अनेक सीटू यूनियनों को कब्जा में कर लिया गया है. उनका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया है. महिला कामगारों के साथ बदसलूक किया जा रहा है. हाल में ही भूम की खेती करने वाली औरतों का असम राइफल्स के जवानों ने बलात्कार किया. यही नहीं सी. पी. एम. के शीर्ष नेताओं की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है.

यह बैठक उदयपुर में बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठी चार्ज की निंदा करती है जिसमें का. नृपेण चक्रवर्ती घायल हुए जब वे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे. कांग्रेस का टी यू जे एस के उग्रवादी गुट टी एन वी के साथ गठजोड़ का मुख्य उद्देश्य राज्य में वामपंथी सरकार को गिराना तथा राज्य में कम्युनिस्ट आंदोलनों को कुचलना था. यह तथ्य हाल में प्रकाशित टी एन

वी के नेता विजय राखाल का प्रधान मंत्री और मिजोरम के कांग्रेसी नेता लालथनहवाला के बीच हुए पत्र व्यवहार से उजागर हुआ।

बैठक त्रिपुरा में कांग्रेस के अर्द्धफासी आतंक का डट कर सामना करने के लिए कामगार तबकों, सीढ़ मजदूरों और जनतांत्रिक ताकतों को गर्मजोशी से बढ़ाई देती है। बैठक सभी राज्य समितियों और सीढ़ यूनियनों का आह्वान करता है कि स्थिति का मुकाबला करें और त्रिपुरा में अर्द्धफासीवादी आतंक के खिलाफ जनमत तैयार करें। बैठक देश के तमाम दूसरे ट्रेड यूनियनों और लोकतांत्रिक ताकतों से अपील करती है कि त्रिपुरा में लोकतन्त्र की रक्षा के लिए चलाये जा रहे लोगों के संघर्ष का समर्थन करें।

पंजाब की स्थिति पर

सीढ़ जनरल काउंसिल की यह बैठक, पंजाब में बेरोकटोक चल रही खालिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियों पर गहरी चिंता प्रकट करती है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद वहां की स्थिति और बदतर हुई है। सरकार धृष्टतापूर्ण ढंग से राजीव-लोगोवाल समझौते को लागू करने, जोधपुर में निर्दोष नजर बन्दियों को रिहा करने तथा दिल्ली दंगा के दोषियों को सजा देने से कतरा रही है। राज्य में निर्दोष लोगों की खुलेआम हत्या वहां का सामान्य जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इस दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीढ़ के समर्थक और कार्यकर्ता तथा किसान नेता बड़ी संख्या में मारे जा चुके हैं।

जनरल काउंसिल उग्रवादियों के एक या दूसरे गुटों के साथ गठजोड़ करने की कांग्रेस की नीति की भर्त्सना करती है। कांग्रेसी सरकार खालिस्तानी उदघोषणाओं के लिए कुख्यात पांच मुख्य ग्रंथियों को रिहा कर दिया है तथा उनसे एक सौदा करने का प्रयास कर रही है। अपने स्वार्थी दृष्टिकोण के कारण कांग्रेस ब्लैकथण्डर के बाद की स्थिति से, जब उग्रवादियों की भर्त्सना की जा रही थी और ये जनता से कट चुके थे, फायदा उठाने में असफल रही।

सरकार राज्य में आतंकवादियों से मुकाबला कर रही लोकतांत्रिक और ट्रेड यूनियन आंदोलनों को कुचलने में जुटी है। यह बैठक राज्य सीढ़ उसकी यूनियनों और अन्य वामपंथी, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष ताकतों का उनके बहादुराना संघर्ष के लिए अभिनन्दन करती है जो देश की एकता व अखण्डता की रक्षा में अपने जान तक की बाजी लगा रहे हैं। बैठक तमाम ट्रेड यूनियनों और विपक्षी पार्टियों से साम्राज्यवादियों के मदद प्राप्त अलगाववादियों के खतरे को महसूस करने तथा देश की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए साझा संघर्ष में शामिल होने की अपील करती है।

फूटपरस्त ताकतों पर

यह जनरल काउंसिल की बैठक देश के विभिन्न भागों में,

लगातार पंगु बना रही तमाम किस्मों की विघटनकारी शक्तियों पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। इस दौरान पंजाब में पृथकतावादी खालिस्तानी उग्रवादियों, त्रिपुरा में टी एन वी, प. बंगाल के दार्जिलिंग जिले में जी एन एल एफ ने बड़ी संख्या में लोगों तथा सीढ़ और दूसरी वामपंथी कार्यकर्ताओं की हत्या कर चुके हैं। इसके अलावा बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि विवाद को लेकर हिन्दू सांप्रदायवादियों तथा मुस्लिम कठमुल्लावादियों ने देश में सांप्रदायिकता को हवा देने में जुटे हैं। पुरी के शंकराचार्य द्वारा प्रोत्साहित हिन्दू पुनर्स्थापनावादी ताकतें और इस तरह की दूसरी शक्तियां, राजस्थान में सती की बर्बर घटना तथा वहां सती मेले के आयोजन के बाद, अपनी गतिविधियां तेज करने में जुटी है। आर एस एस, भाजपा और शिव सेना जैसी कट्टर सांप्रदायिक ताकतें अपने आप को स्थापित करने के लिए जनता में जाति, समुदाय और वर्ण के आधार पर लगातार फूट डालने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अलग उत्तराखण्ड की मांग बार बार उठायी जा रही है। अलगाववादी ताकतों की गतिविधियां अभी भी देश तथा जनता की एकता को छिन्न-भिन्न करने में बेरोकटोक जारी है। इसके बावजूद कांग्रेस (आई) देश की एकता, अखण्डता और प्रभुसत्ता को नजरअंदाज कर केवल अपनी संकीर्ण चुनावी हितों को बढ़ावा देने के लिए इन एक या अन्य ताकतों से सिद्धांतहीन स्वार्थी समझौता करने पर लगी हुई है।

यह जनरल काउंसिल, सीढ़ की पंजाब, प. बंगाल, त्रिपुरा और केरल की राज्य शाखाओं को इन सांप्रदायिक और फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ संघर्ष चलाने के लिए मुख्य तौर पर बढ़ाई देती है। साथ ही सभी राज्य कमेटियों का केंद्रित ध्यान आकृष्ट करना चाहती है कि इन विघटनकारी और मौकापरस्त शक्तियों के खिलाफ देश में चल रहे संघर्ष आमतौर पर कमजोर है। लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को इस संघर्ष में पूरी तरह से अब तक लामबन्द नहीं किया जा सका है। ट्रेड यूनियनों ने इस तथ्य को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाये हैं कि इन विघटनकारी ताकतों के पीछे साम्राज्यवादी शक्तियां सक्रिय हैं।

इन विघटनकारी ताकतों के विरुद्ध जन चेतना जगाने तथा इन ताकतों के साथ सरकार की समझौतावादी नीतियों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी सीढ़ को उठानी है। बैठक सीढ़ की तमाम यूनियनों और राज्य कमेटियों से अपील करती है कि वे इन फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने के अपने प्रयासों को दुगुना करें और जब कभी भी ये शक्तियां अपना सर उठाएं तब हस्तक्षेप करें और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें एवं अधिकाधिक कामगारों और ट्रेड यूनियनों को लामबंद करें।

श्रीलंका पर

जनरल आउंसिल अब तक कायम श्रीलंका की गम्भीर हालात पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। श्रीलंका और भारत

सरकार के बीच हुए समझौता श्रीलंका में लम्बे अर्से से चल रहे जातीय दंगों का संतोष जनक हल के लिए जमीन तैयार की थी तथा श्रीलंका को अस्थिर बनाने और दोनों गुटनिरपेक्ष देशों के बीच दरार डालने की साजिश करने वाली साम्राज्यवादी ताकतों पर कुठाराघात की थी. लेकिन एल टी टी ई के द्वारा इस समझौता का उल्लंघन और सिंहली उग्रवादियों द्वारा इस समझौते के बहिष्कार के कारण वहां की स्थिति गम्भीर बन गई. इन उग्रवादियों के हाथों श्रीलंका के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं समेत अनेक वामपंथी और लोकतांत्रिक नेता मारे जा चुके हैं. मीटिंग श्रीलंका की एकता और अखण्डता को बरकरार रखने के लिए इस जातीय समस्या का हल ढूंढने की दिशा में सात दलों का समाजवादी गठबन्धन के गठन का स्वागत करती है तथा इस मसले पर एक सैद्धांतिक नजरिया अपनाने के लिए उन्हें बधाई देती है.

मीटिंग आशा करती है कि भारतीय शांति सेनाओं द्वारा युद्ध विराम की घोषणा पर एल टी टी ई अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी और वहां की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए चुनाव में शांतिपूर्ण ढंग से भाग लेगी.

बेरोजगारी पर

धनबाद में संपन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक, हाल में तेज रफ्तार से बढ़ती बेरोजगारी पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है. एक तरफ तो सरकार की पूंजीवादी रास्ते पर आर्थिक विकास की नीति बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है तो दूसरी तरफ अंधाधुंध कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण के कारण उत्पन्न स्थिति इस स्थिति को और गम्भीर बना रही है. तेजी से फैल रही औद्योगिक बीमारी जिसके कारण मिलें बंद हो रही है, बेरोजगारों की कतारों को दिन व दिन लम्बी बनाती जा रही है.

श्रम नियोजनालय के रजिस्ट्रारों के आधार पर बने बेरोजगारों के आंकड़े देश में बेरोजगारी के आधे-अधुरे तस्वीर प्रस्तुत करते हैं. इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के आधार पर देश में बेरोजगारों की संख्या तीन करोड़ से ऊपर है जबकि अनुमान है कि ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या सात करोड़ के लगभग है.

इस बदतर स्थिति को देखते हुए यह मीटिंग जोरदार ढंग से मांग करती है कि सरकार संविधान में काम के अधिकार को बुनियादी अधिकार के रूप में शामिल करे. मीटिंग पुनः मांग करती है कि रोजगार की तलाश में लगे प्रत्येक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मुहैया कराने के लिए अविलम्ब कानून बनाएं.

मीटिंग संतोष के साथ इस बात को नोट करती है कि कुछ राज्य कमेटियों ने बेरोजगारों को संगठित करने, सम्मेलन आयोजित करने और दूसरे कार्यक्रम चलाने के क्षेत्र में पहल कदमी कर रही है. किंतु इस समस्या के विशालता को देखते हुए इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता. यह मीटिंग सभी सीटू की

राज्य कमेटियों और यूनियनों से बेरोजगारों के विशाल फौजों को लामबंद करने, उनके लिए कार्यकारी योजनाएं बनाने तथा सीटू के बम्बई सम्मेलन की अपील के अनुसार राजधानी मार्च की योजना को अंजाम देने के लिए अपने प्रयास दुगुनी करने की अपील करती है.

किसान आंदोलन के प्रति एकजुटता पर

सीटू जनरल काउंसिल की यह मीटिंग, किसान सभाओं, खेतिहर कामगारों के संगठनों और देश के करोड़ों किसानों और खेत मजदूरों का उनके 15 सितम्बर को समाप्त पक्षकाल व्यापी शानदार आंदोलनों के लिए गर्मजोशी से बधाई देती है. करीब 20 लाख आंदोलनकारियों ने काफी अर्से से लंबित पड़ी ज्वलंत मांगों जैसा भूमिसुधार, लाभकारी दाम, कर्ज और कर राहत, न्यूनतम मजदूरी, खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून, बेरोजगारी उन्मूलन इत्यादि को लेकर गिरफ्तारियां दी. इस आंदोलन का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह था कि इस आंदोलन की अगुआई चार वामपंथी दलों—सी पी आइ (एम), सी पी आइ, आर एस पी और फारवर्ड ब्लॉक के जनसंगठनों ने संयुक्त रूप से किया था. यह नीहित ग्रामीण स्वार्थों से मुक्त खेतीहर मजदूरों और किसानों के बीच बढ़ती एकजुटता का इजहार करता है. इस एकजुटता से कृषिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त होगा.

मीटिंग प्रदर्शनकारियों पर सरकार के दमनात्मक कार्रवाइयों की निंदा करती है. त्रिपुरा में बर्बर लाठीचार्ज में सी पी आइ (एम) पोलिट ब्यूरो के सदस्य का. नृपेन चक्रवर्ती घायल हुए थे.

यह मीटिंग इस किसान आंदोलन का पूर्ण समर्थन करने तथा उनके साथ गिरफ्तारी देने के लिए सीटू यूनियनों और उनसे संबद्ध कामगारों को बधाई देती है. मीटिंग कामगारों से अपील करती है कि उनके अधिकारों के प्रति अपना समर्थन कायम रखे और मजदूरों तथा किसानों के जुझारू गठबंधन स्थापित करें.

कामकाजी महिलाओं पर

धनबाद में आयोजित यह जनरल काउंसिल की बैठक भारत बंद और दूसरे हड़ताली कार्रवाइयों में भारी संख्या में भाग लेने तथा इस दौरान पुलिस के दमन का डट कर मुकाबला करने के लिए कामकाजी महिलाओं का अभिनन्दन करती है. मीटिंग इस बात पर पुनः संतोष व्यक्त करती है कि विभिन्न राज्यों और औद्योगिक क्षेत्रों में आम ट्रेड यूनियन आंदोलनों में तथा अपनी खास मांगों को लेकर कामकाजी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है.

बढ़ते संघर्ष की पृष्ठभूमि में, बैठक इस बात की ओर ध्यान खींचना चाहती है कि यद्यपि कुछ राज्य कमेटियों ने कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के लिए कुछ प्रयास चलाया है फिर

भी यह स्थिति की मांग के अनुरूप कतई नहीं है, कामगार महिलाओं की समन्वय समितियों के गठन और उन्हें लगातार ट्रेड यूनियन गतिविधियों में शामिल करने और उनके खास मांगों को लेकर संघर्ष चलाने के लिए शायद ही कोई गंभीर प्रयास चलाया गया है।

कामगार महिलाओं में बढ़ते जागरूकता को देखते हुए यह बैठक अपने राज्य कमेटियों तथा यूनियनों को निर्देश देती है कि वह कामगार महिलाओं की समन्वय समितियाँ बनाएं, यूनियनों की नीति निर्धारण समितियों में तथा ट्रेड यूनियन कार्रवाइयों में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें और उनके समर्थन में कार्रवाई का कार्यक्रम तय करें।

अधिक न्यूनतम मजदूरी के लिए संघर्ष पर

घनबाद में 23 से 25 सितंबर 1988 तक हुई सीटू जनरल काउंसिल की बैठक, लाखों असंगठित मजदूरों को समुचित न्यूनतम वेतन से वंचित रखने की भारत सरकार की नीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराती है, इस नीति के चलते इन मजदूरों को गरीबी की रेखा से नीचे रखा जा रहा है।

विभिन्न राज्यों में तय की गयी मजदूरियाँ बहुत कम हैं और कुछ राज्यों में तो उन्हें भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है। सरकारी तौर पर तय की गई मजदूरी में नियमित रूप से जो सुधार होना चाहिए वह भी नहीं किया जाता है। अनेक राज्यों में, न्यूनतम मजदूरी को किसी मूल्य सूचकांक से नहीं जोड़ा गया है जिससे इन मजदूरों के जीवन स्तर में लगातार गिरावट आ रही है।

इन राज्यों में श्रम कानूनों का लागू न किया जाना एक आम बात है और प्रशासन, इन कानूनों का उल्लंघन करने वाले मालिकान के खिलाफ कदम उठाने में विफल रहता है, ठेका मजदूरी प्रथा जारी है जिसके चलते, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में ही काम देनेवाले मूल संस्थानों की मिलीभगत से, सब कुछ निचोड़ पर आमादा ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का निर्भम शोषण जारी है। जनकल्याण सुविधाओं, सुरक्षा प्रावधानों, आवास सुविधाओं आदि के अभाव ने, इन मजदूरों की दयनीय हालत को बदतर बनाने का ही काम किया है।

जनरल काउंसिल, विभिन्न राज्यों में सीटू इकाइयों को बधाई देती है जिन्होंने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोत्तरी का मुद्दा ईमानदारी से उठाया है और न्यूनतम मजदूरी बढ़वाने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर संघर्ष छेड़े हैं। बहरहाल, सीटू यह महसूस करती है कि एक देशव्यापी आंदोलन के बिना, इस संघर्ष को और आगे नहीं ले जाया जा सकता है।

जनरल काउंसिल देश भर की तमाम सीटू यूनियनों का आह्वान करती है कि 31 अक्टूबर का दिन प्रदर्शनों, रैलियों तथा धरनों के आयोजन के जरिए अखिल भारतीय न्यूनतम

मजदूरी बढ़ोत्तरी दिवस के रूप में मनाएं और देश भर में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोत्तरी का प्रचार करें।

जनरल काउंसिल पश्चिम बंगाल तथा केरल की सरकारों को बधाई देती है जिन्होंने हाल ही में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोत्तरी की है।

सीटू, सभी ट्रेड यूनियनों से अपील करती है कि एकजुट होकर, व्यापक आधार पर देशव्यापी आंदोलन संगठित करें ताकि न्यूनतम मजदूरी बढ़वायी जा सके।

जनरल काउंसिल, 1050 रु. की न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर, एक हफ्ते की हड़ताल करने के सीटू की दिल्ली राज्य कमेटियों के फैसले का स्वागत करती है और इसी सप्ताह के दौरान अपने-अपने राज्यों में हड़ताल समेत सुनियोजित संघर्ष संगठित करने के सीटू की दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तथा गुजरात राज्य कमेटियों के प्रतिनिधियों की बैठक के फैसले का स्वागत करती है।

जनरल काउंसिल, अन्य राज्यों की सीटू यूनियनों से अपील करती है कि इस संघर्ष के साथ एकजुटता प्रकट करें, ताकि न्यूनतम मजदूरी के लिए संयुक्त कार्रवाई एक देशव्यापी आंदोलन का रूप ले सके और भारत सरकार पर असंगठित मजदूरों के प्रति अपनी नीति बदलने के लिए दबाव डाला जा सके ताकि उनकी जिदगी तथा काम की स्थिति में निरन्तर सुधार हो।

ट्रेड यूनियन विरोधी विधेयकों पर

यह जनरल काउंसिल, अनेक ट्रेड यूनियनों के विरोध की उपेक्षा करते हुए राज्य सभा में चोरी छिपे ढंग से ट्रेड यूनियन और औद्योगिक विवाद कानून संशोधन विधेयक पेश करने के लिए भारत सरकार की जोरदार भर्त्सना करती है। राज्य सभा में ठीक उसी ढंग से हास्पिटल और दूसरे विधेयक पारित करवाने के लिए भी वह सरकार की निंदा करती है। मीटिंग इस विधेयक के वापस लिए जाने की मांग को लेकर जबर्दस्त विरोधी कार्रवाई संगठित करने के लिए अस्पताल कर्मचारियों, नर्सों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों कामगारों सहित मजदूरों और कर्मचारियों का गर्मजोशी से अभिनन्दन करती है। 14 जुलाई के सम्मेलन में इस दमनकारी विधेयक के विरोध में कामगारों और कर्मचारियों के तमाम तबकों की सबसे बड़ी लामबन्दी देखी गई। ये दो विधेयक ट्रेड यूनियनों की आजादी, हड़ताल का अधिकार पर सरकार का सबसे कड़ा हमला है। वर्तमान औद्योगिक संबंध मशीनरी की जगह पर औद्योगिक संबंध आयोग की स्थापना का प्रवधान इस विधेयक का सबसे काला पहलू है। दरअसल यह, किसी भी कानूनी हड़ताल को लगभग असंभव बनाने का एक सरकारी संयंत्र होगा। ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए गुप्त मतदान का जनतांत्रिक मांग को ठुकराते हुए इस

बिल में, मजदूरों पर पिछू युनियनों को थोपने के इरादे से आपत्तिजनक चेक ऑफ प्रणाली का प्रावधान है। यह दोनों काले विधेयक, सरकार की नीतियों के खिलाफ हर तबके के मजदूर-कर्मचारियों के बढ़ते संघर्ष को रोकने के इरादे से ट्रेड युनियन आंदोलन पर ही अंकुश लगा देने की एक साजिश है।

जनरल काउंसिल की यह बैठक इन काले विधेयकों को संपूर्णरूप से वापस लेने के लिए सरकार से मांग करती है। जनरल काउंसिल, मजदूरों व ट्रेड युनियनों का आह्वान करता है कि वह अपनी एकता को और मजबूत करें तथा इन विधेयकों को पूरी तरह रद्द करने की मांग पर एक देश व्यापी हड़ताल कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जनरल काउंसिल जनवादी ताकतों से यह अपील भी करती है कि इस तानाशाही मुहिम के खिलाफ, मजदूरों के संघर्ष का साथ दें।

मानहानी विधेयक पर

सीटू की यह जनरल काउंसिल की बैठक प्रेस और जनता के सभी वर्गों को मानहानी विधेयक के खिलाफ उनकी उल्लेखनीय एकजुट संघर्ष, जिसने राजीव सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, के लिए हार्दिक बधाई देती है। त्रिपुरा में अधिनायकवादी हमले, 59वां संविधान संशोधन, मजदूर विरोधी काले विधेयकों के बाद मानहानी विधेयक प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति के बुनियादी अधिकार पर करारा प्रहार था।

इस परिस्थिति में प्रेस ने अभूतपूर्व एकता का प्रदर्शन करते हुए इस विधेयक के वापसी को लेकर संघर्ष के रास्ते पर उतर आए। इस विधेयक के असली रूप को देख कर इसके जबर्दस्त विरोध में भारतीय जनता के अनेक तबकों ने अपनी आवाज बुलन्द की। इस विधेयक का उद्देश्य सरकार में उच्च स्तर पर और मंत्रियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को बेनकाब होने से रोकना था।

राष्ट्रव्यापी विरोधी कार्रवाई और 6 सितंबर को प्रेस के सम्पूर्ण हड़ताल ने सरकार को यह घोषणा करने पर मजबूर कर दिया कि इस विधेयक का कानून नहीं बनाया जाएगा। जनरल काउंसिल प्रेस, देश के लोकतांत्रिक ताकतों और ट्रेड युनियन आंदोलनों से अपील करती है कि वे अपनी एकता को और मजबूत करें, सरकार की अधिनायकवादी कदमों के प्रति चौकन्ना रहे और उसके खिलाफ डट कर विरोध करें तथा एकजुट होकर प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति के अधिकार को बचाये रखें।

सीमेंट मजदूरों के संघर्ष पर

जनरल काउंसिल सीटू, एटक, एच. एम. एस. और बी. एम. एस. के मांग पत्र पर विचार विमर्श करने से हिचकने और केवल इंटक के प्रतिनिधियों को लेकर आर्बिट्रेशन बोर्ड (सुलहकारी निकाय) की स्थापना के लिए सरकार और सीमेंट मैन्युफैक्चर्स एसोसियेशन की निंदा करती है। इस तथ्य के बावजूद कि इंटक

मजदूरों के बड़े तबकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है सरकार और इंटक में खुली मिलीभगत है। सुलहकारी बोर्ड का थोपा जाना मजदूरों के सामूहिक सौदेबाजी और वेतन वार्ताओं में दूसरे ट्रेड युनियनों के हिस्सेदारी के अधिकार को नकारता है।

यह बैठक डालमिया की कम्पनी उड़ीसा सीमेंट के प्रबंधकों द्वारा वेतन वार्ता की मांग पर आंदोलन कर रहे मजदूरों पर समाजविरोधियों द्वारा हमला करवाये जाने की तीव्र निंदा करती है। यह बैठक सरकार से मांग करती है कि आर्बिट्रेशन बोर्ड को खत्म करके मांग पत्र पर समझौते के लिए सभी संबद्ध युनियनों से बातचीत करे। साथ ही अन्तिम समझौता होने तक पर्याप्त अन्तरिम भत्ता देने की भी यह बैठक मांग करती है। यह मीटिंग सभी ट्रेड युनियनों से अपील करती है कि सरकार को इस मांग पर राजी करने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें।

मद्रास फटिलाइजर में ठेका मजदूरों के संघर्ष पर

जनरल काउंसिल उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने और सीटू युनियन को विघटित करने के उद्देश्य से मनाली युनिट के ठेका मजदूरों पर बर्बर हमला करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के मद्रास फटिलाइजर के प्रबंधकों की तीव्र भत्सना करती है। जब मजदूरों ने अपने युनियन में सीटू के नेतृत्व को स्वीकार किया तब प्रबंधकों ने एकतरफा रूप से ठेका मजदूरों को फैक्टरी में आने से रोका और दूसरे मजदूरों को काम देने का प्रयास किया। इस तरह इसने नये मजदूरों को काम में नहीं लगाये जाने तथा इस विवाद को युनियन के साथ बातचीत कर सुलझाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया। ऊपर से प्रबंधकों ने युनियन के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस द्वारा पिटाया और उन्हें भूटे मुकदमों में फंसाया।

बैठक, सरकार और प्रबंधक से उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए इस विवाद को अविलम्ब निपटाने की मांग करती है और मजदूरों का आह्वान करती है कि वे अपनी मांगों के निपटारे के लिए अपना संघर्ष आगे बढ़ाएं।

निर्माण मजदूरों के लिए व्यापक केन्द्रीय कानून पर

जनरल काउंसिल का यह अधिवेशन निर्माण मजदूरों के लिए व्यापक केन्द्रीय कानून बनाने से इकार करने के लिए भारत सरकार की निंदा करती है।

इस तथ्य के बावजूद कि निर्माण उद्योग देश भर में व्यापक एवं भिन्न-भिन्न कार्य क्षेत्र के लिए सबसे अधिक संख्या में मजदूरों की भर्ती करती है, मजदूरों के इन विशाल वर्ग के लिए किसी तरह का कानूनी संरक्षण, नौकरी की सुरक्षा, काम में तथा उनके काम करने की स्थिति में एकरूपता नहीं है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के निर्माण उद्योग में नियमित मजदूरों की नौकरी, स्थाई रूपी काम को पूरी तरह या आंशिक तौर पर ठेके पर देने की निति के कारण खतरे में पड़ गई है।

जनरल काउंसिल अविलम्ब व्यापक केन्द्रीय कानून लागू करने की मांग करती है ताकि देश भर के निर्माण मजदूरों के लिए नौकरी की गारंटी और सेवा शर्तों में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके. बैठक निर्माण मजदूरों से अपील करती है कि वे अपने मांगों की पूर्ति को लेकर अपना एकजुट संघर्ष जारी रखें.

मेटल वाक्स में तालाबंदी पर

धनबाद में सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल की बैठक, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कोचीन, फरीदाबाद में मेटल वाक्स फैक्टरी में पिछले 8 से 10 महीनों से चल रही तालाबंदी पर गंभीर चिंता प्रकट करती है. यह मीटिंग इस गैर कानूनी तालाबंदी को बरकरार रखने के लिए प्रबन्धकों की निंदा करती है जबकि सम्बद्ध राज्य सरकारों ने इसकी स्वीकृति देने से इंकार कर चुकी है. इन इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए वेतन में 20 प्रतिशत कटौती, डी ए को समाप्त करने आदि जैसी जघन्य प्रतिगामी शर्तों को रखने की प्रबन्धकों के कार्रवाई की भी बैठक निंदा करती है. बैठक इन प्रतिगामी शर्तों को मान लेने के लिए मजदूरों को विवश करने के लिए सरकार और बी आई एफ आर की निंदा करती है.

यह बैठक प्रबन्धकों और सरकार से बिना किसी शर्त के तालाबंदी अविलम्ब खत्म करने की मांग करती है साथ ही मजदूरों से अपील करती है कि वे अपने पक्ष को लेकर अपनी एकजुट लड़ाई जारी रखें.

गोदी और बंदरगाह मजदूरों पर

सीटू जनरल काउंसिल की बैठक, गोदी और बन्दरगाह मजदूरों के राष्ट्रीय फेडरेशन की ओर से रखी गयी साझा मांग पत्र को सुलझाने की दिशा में गोदी और बन्दरगाह के प्रबन्धकों की नकारात्मक रवैया की निंदा करती है. हालांकि वेतनमान पर बातचीत के लिए द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति की छः मीटिंग हुई हैं किन्तु प्रबंधक ने इन मांग पत्रों पर कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त किया है. इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नाम पर इन मजदूरों के वर्तमान अधिकारों को वापस लेने तथा उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में कटौती करने सम्बन्धी कई प्रतिगामी प्रस्ताव प्रबंधन ने पेश किया है.

मीटिंग बन्दरगाह के विकास के दायित्व उठाने से हिचकने तथा बन्दरगाह के विभिन्न कार्य क्षेत्रों को निजी मालिकों के हाथ में सौंपने के संस्कार के प्रयास पर गहरी चिंता प्रकट करती है.

यह मीटिंग, सरकार से इन साझा मांग पत्रों के अविलम्ब निपटारे की मांग करती है और गोदी और बन्दरगाह मजदूरों का आह्वान करती है कि बन्दरगाहों को निजीकरण करने के

सरकार के कदम के खिलाफ तथा अपनी मांगों के समर्थन में एकजुट होकर संघर्ष करें.

उड़ीसा के चिकित्सकों और कॉलेज शिक्षकों के आंदोलन पर

धनबाद में सम्पन्न सीटू की यह जनरल काउंसिल बैठक, उड़ीसा के चिकित्सकों और शिक्षकों को आर्थिक मांगों पर उनके आंदोलन के लिए गर्मजोशी से बधाई देती है. बैठक, विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के सिफारिशों को लागू करने के शिक्षकों के मांग पर अपना समर्थन जाहिर करती है. बैठक उन पर क्रूर लाठी चार्ज की निंदा करती है तथा उड़ीसा सरकार से इन विवादों के अविलम्ब निपटारे की मांग करती है.

कोलियरी स्कूलों के शिक्षकों की मांग पर

सीटू जनरल काउंसिल की यह बैठक, कोयला खादान क्षेत्रों के बच्चों के शिक्षा के प्रति खादान प्रबंधकों की लापरवाहीपूर्ण रुख की भर्त्सना करती है.

कोल इंडिया लिमिटेड तथा दूसरे कोयला क्षेत्रों के अधिकारियों ने अफसरों के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर रुचि ले रहे हैं. किन्तु वे कोयला मजदूरों के बच्चों के शिक्षा पाने के प्राथमिक अधिकार के प्रति उपेक्षा का रुख अख्तियार करते हैं. पिछले वेतन समझौते के दौरान प्रबंधक शिक्षा के मद में व्यय को 2.5 करोड़ रुपये से बढ़ाने पर राजी हुआ था किन्तु जिस तरह से ये पैसे खर्च किए जा रहे हैं उस पर सीटू गहरा असंतोष प्रकट करती है. शिक्षा संस्थान को दिए जाने वाले वित्तीय बजट का व्यापक पैमाने पर गलत रूप से इस्तेमाल होता है तथा शिक्षकों को कम वेतन दिया जाता है. इन्हें न तो नौकरी की गारंटी है न पदोन्नति का कोई रास्ता मिलता है और न ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने में इन्हें कोई सुविधा दी जाती है.

सीटू, कोयला खादान शिक्षक मोर्चा द्वारा उठाये गए कोयला खादानों के शिक्षकों के मांग का पूर्ण समर्थन करती है और कोयला खादान प्रबंधकों से कोयला खादान क्षेत्रों के लिए बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के मांग को मान लेने के लिए आग्रह करती है.

सीटू कोयला क्षेत्र के शिक्षकों को हार्दिक बधाई देती है तथा उनसे अपनी एकता मजबूत करने और उनकी मांगों के माने जाने तक और अधिक दृढ़ता से आंदोलन चलाने का आह्वान करती है. सीटू सभी ट्रेड यूनियनों से इन शिक्षकों के मांगों का समर्थन करने की अपील करती है.

पोर्टब्लेयर के नाविकों के आंदोलन पर

धनबाद में सम्पन्न सीटू जनरल काउंसिल की बैठक शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया और अन्दमान-निकोबार द्वीप समूह के

प्रबंधकों द्वारा पोर्टब्लेयर के संघर्षरत नाविकों पर चलाए जा रहे हमले की तीव्र भर्त्सना करती है।

यह बैठक, इस बात को गंभीर चिंता के साथ नोट करती है कि शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रबंधकों ने अन्दमान स्थित नाविकों के 1985 से लम्बित पड़े मांग पत्र पर, जिसके समर्थन में ये मजदूर संघर्षरत हैं, समझौता करने के बजाय उनके स्थान पर नयी बहाली कर पुलिस व गुण्डों से हमला करवाकर मजदूरों को हटाने की साजिश में लगे हैं।

(पृष्ठ 4 का शेष)

3. किसी को काम से निकाले बिना उद्योग का पुनर्गठन किया जाय।

4. बन्द अथवा लाक आउट की गयी सभी मिलों को सरकार, उद्योग का पूरा राष्ट्रीयकरण होने तक अपने हाथ में ले ले।

5. पावरलूम मजदूरों की कम तनखाहों को काफी बढ़ाया जाय और पक्की तौर पर उन्हें दूसरी सुविधाएं दी जायं। इन मजदूरों के सिलसिले में भी श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा के कदमों और न्यूनतम तनखाह लाजिमी तौर पर दिये जाने की गारंटी की जाय।

6. हैंडलूम उद्योग के लिए आवश्यक क्वालिटी का सूत पक्की तौर पर रिजर्व रखा जाय और रियायती दर पर सप्लाई किया जाय। उचित दाम पर उनका माल खरीदने की गारंटी हो और हैंडलूम मजदूरों की न्यूनतम पगार गरीबी की सीमा से नीचे न हो।

7. मोटे कपड़े पर एक्साइज ड्यूटी रद्द की जाय, साधारण कपड़े पर कम की जाय और गारंटी की जाय कि सुविधा उपभोक्ता को मिले।

8. घरेलू जूजर को पूरा किए बगैर कपास या सूत का निर्यात न किया जाय।

9. कपास-उत्पादकों को उचित भाव की गारंटी दी जाय।

10. धंधे बंद होने से बेकार हो गये सभी मजदूरों को पर्याप्त सहायता और मुआवजा फौरन दिया जाय।

11. ठेके पर मजदूरों की भर्ती बंद की जाय।

कपड़ा मजदूरों की अखिल भारतीय कन्वेंशन, सारे देश के कपड़ा मजदूरों का आह्वान करती है कि वे इन मांगों के समर्थन में आंदोलन चलाएं।

कन्वेंशन, 21 नवंबर को देश भर में "कपड़ा उद्योग बचाओ दिवस" मनाने का फैसला करती है। प्रदर्शनों, मीटिंगों, धरनों, सम्मेलनों, सेमिनारों आदि के जरिए यह दिन मनाना चाहिए, ताकि सरकार की टेक्सटाइल नीति के विरोध में मजदूरों और आम लोगों को लामबंद किया जा सके।

कन्वेंशन, लाखों हस्ताक्षर जमा करने का फैसला करती है, जो 5 दिसम्बर को संसद की पेटीशन कमेटी के अध्यक्ष को दिये जायेंगे।

यह कन्वेंशन, राजनीतिक भिन्नताओं के बावजूद सभी ट्रेड यूनियनों से अपील करती है कि वे मांगों के समर्थन में संयुक्त संघर्ष बढ़ाने के लिए आंदोलन को जोरदार बनाएं।

अन्दमान स्थित नाविकों के बहादुराना संघर्ष के प्रति सम्पूर्ण एकजुटता का इजहार करते हुए सीटू, शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया से आग्रह करती है कि वह अपने तमाम मजदूर विरोधी कार्रवाइयों को बन्द करें तथा तीन साल से पड़ी मांग पत्र का निपटारा करें।

सीटू, अन्दमान के मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वहां के घरेलू वारिंजियक पोतों में कार्यरत नाविकों का साथ दें और उनके संघर्ष की कामयाबी के लिए हर संभव मदद दें।

(पृष्ठ 5 का शेष)

श्रृंखला तैयार की है। जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम मंत्रालय की सिफारिशों के खिलाफ है। नयी श्रृंखला का वेटेज डायग्राम मजदूर वर्ग के परिवारों के उपयोग स्तर और उपयोग पद्धति पर आधारित नहीं है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने रथ कमेटी की सर्वसम्मत सिफारिशों का खुला उल्लंघन किया है।

सरकार ने आवास भत्ता, उचित दर की दुकान, राशन वस्तुओं, कीमत संग्रहिका मशीनरी आदि के मामले में भी रथ कमेटी का महत्वपूर्ण सिफारिशों को आज तक स्वीकार नहीं किया है। इन सिफारिशों को स्वीकार किए बगैर जो सूचकांक तैयार होगा वह नीचे ही रहेगा और इसकी मार मजदूर वर्ग पर पड़ेगी। रथ कमेटी ने सूचकांक में 7 प्वाइंट्स से सुधार की सिफारिश की थी। सरकार ने ऐसा न करके मजदूरों को करोड़ों रुपये के महंगाई भत्ते से वंचित कर दिया। भारत सरकार तो मौजूदा सूचकांक श्रृंखला को भी दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है।

हम 1960 की श्रृंखला को समाप्त करने का कड़ा विरोध करते हैं। वास्तव में हम चाहते हैं कि मौजूदा श्रृंखला में जारी हेराफेरी को समाप्त किया जाय। हम नयी श्रृंखला के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उसकी गणना वैज्ञानिक पद्धति से होनी चाहिए। यद्यपि भारत सरकार ने 1970 की श्रृंखला भी तैयार की थी लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। 1982 की श्रृंखला पर भी वे ही चीजें लागू होती हैं।

1960 की श्रृंखला के बारे में 1968 के भारतीय श्रम सम्मेलन के फैसले यद्यपि अभी वैध हैं लेकिन उन्हें 1980 की श्रृंखला पर लागू नहीं किया जा सकता इसलिए उन दो श्रृंखलाओं के बीच समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है।

इस लिए, हम मांग करते हैं कि 1982 को आधार वर्ष बनाकर नयी श्रृंखला लागू करने से पहले भारत सरकार आइ एल ओ की हिदायतों का सम्मान करे तथा रथ कमेटी की सर्वसम्मत सिफारिशों को मंजूर करे। हमारी मांग है कि ट्रेड यूनियनों के सहयोग से पारिवारिक बजटों का ताजा अध्ययन किया जाय ताकि एक वैज्ञानिक सूचकांक प्रणाली लागू की जा सके। रथ कमेटी ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी।

यदि ट्रेड यूनियन आंदोलन के विरोध के बावजूद भारत सरकार मनमानी करते हुए नयी श्रृंखला लागू करती है तो उसे मजदूर वर्ग के एकजुट प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह भारत सरकार पर ही होगी।